AIM Awaken India Movement
awakenindiamovement.com
www.awakenindiamovement.com
mail2aim@protonmail.ch

प्रेस विज्ञप्ति

अवेकन इंडिया मूवमेंट ने कोविशील्ड वैक्सीन के दुष्प्रभावों पर चिंता जताई

दिनांक: 6 मई 2024

हाल ही में जहां एस्ट्राजेनेका ने यूके की अदालतों में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम (टीटीएस) के साथ थ्रोम्बोसिस को एक साइड इफेक्ट के रूप में स्वीकार किया है, अवेकन इंडिया मूवमेंट (एआईएम), सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन की सुरक्षा पर गहरी चिंता व्यक्त करता है। अन्य कोविड टीके जिन्हें आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के तहत और नैदानिक परीक्षण पूरा किए बिना अनुमोदित किया गया था।

साइड इफेक्ट के रूप में टीटीएस की स्वीकृति: दुनिया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम (टीटीएस) के साथ थ्रोम्बोसिस नामक कोविड वैक्सीन के दुष्प्रभाव के बारे में जान रही है।

- लेकिन, भारत सरकार को इसके बारे में मई 2021 में 33 वर्षीय फ्रंटलाइन वर्कर स्नेहल लुनावत की मौत के बाद पता चला, जिनकी कोविशील्ड वैक्सीन लगने के बाद मौत हो गई थी। उनकी मृत्यु की पुष्टि राष्ट्रीय एईएफआई समिति ने वैक्सीन उत्पाद संबंधी प्रतिक्रिया - ए1 मृत्यु के रूप में की थी, फिर भी हमारी सरकार वैक्सीन निर्माताओं से खुलासे की मांग करने में विफल रही।
- मदद के लिए पूछे जाने पर, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट (एसआईआई) ने इस बात से इनकार किया कि उनका टीका टीटीएस का कारण बन सकता है, उन्होंने भी अक्टूबर 2021 में चुपचाप इसे अपने टीके के उत्पाद सम्मिलन में जोखिम के रूप में शामिल कर लिया।
- सामान्य लोग वैक्सीन के उत्पाद सम्मिलन से कितना समझ सकते हैं? न तो हमारी सरकार ने दुष्प्रभावों की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी और न ही हमारे डॉक्टर उनसे निपटने के लिए तैयार थे।
- यदि ऐसा किया जाता, तो 18 वर्षीय रितिका जैसी कई जिंदगियां बचाई जा सकती थीं, जहां डॉक्टरों ने टीटीएस से बेखबर होकर वायरल संक्रमण के कारण उसका इलाज किया, जबकि उसके परिवार ने उन्हें हाल ही में टीकाकरण के बारे में चेतावनी दी थी।

बढ़ती मौतें और प्रतिकूल घटनाएँ: अवेकन इंडिया मूवमेंट (एआईएम) भारत में मीडिया/सोशल मीडिया द्वारा कवर किए गए कोविड वैक्सीन से होने वाली मौतों का विवरण एकत्र कर रहा है और देश के विभिन्न उच्च अधिकारियों के साथ साझा कर रहा है। सरकार इन मौतों की जांच के हमारे अनुरोध का जवाब देने

में बार-बार विफल रही है। वर्तमान संख्या में वयस्क आबादी में 19,273 मौतें और बच्चों में 186 मौतें हैं। विवरण वाली फ़ाइलें नीचे दिए गए लिंक में पाई जा सकती हैं:

https://drive.google.com/drive/folders/1BTC9Mjszo0CvxvVyyte6aR-uYNmoEOGM?usp=sharing

सरकार ने कोविड टीकाकरण के बाद दुखद मौतों के बढ़ते मामलों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है और फिर भी वह उन्हें "सुरक्षित और प्रभावी" के रूप में प्रचारित कर रही है। हम चाहते हैं कि भारत सरकार और उसकी नौकरशाही यह जाने कि भारतीय नागरिक वैश्विक फार्मास्युटिकल उद्योग के लिए गिनी पिग नहीं हैं। यदि वे भारतीय नागरिकों के जीवन को खतरे में डालते हुए बिग फार्मा को लाभ पहुंचाने वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों को आगे बढ़ाना जारी रखते हैं, तो इसके परिणामस्वरूप देशव्यापी आंदोलन और विरोध प्रदर्शन होंगे।

कोविड टीकों के अन्य घातक दुष्प्रभाव - लाभों की तुलना में जोखिम कहीं अधिक हैं: जब कोविड-19 टीके लगाए गए, तो बहुत से लोगों को पता नहीं था कि उनके चरण -3 परीक्षण पूरे नहीं हुए थे, जिसका अर्थ है कि निर्माताओं के पास भी संभावित दुष्प्रभावों, अल्पकालिक या दीर्घकालिक या घातक पर पूरा डेटा नहीं था। मामला। टीके से होने वाली चोटों के बारे में पहले से ही कम जागरूकता के साथ, विशेष रूप से भारत में, लोगों को पता नहीं था कि इन अजीब विसंगतियों की रिपोर्ट कहां करें, लेकिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट के अलावा। हजारों महिलाओं ने अपने मासिक धर्म चक्र में असामान्यताओं की सूचना दी, जिसकी पुष्टि सितंबर-2022 में प्रकाशित एक अध्ययन में टीके के दुष्प्रभाव के रूप में की गई।
वर्तमान में, यूरोपीय मेडिकल एजेंसी संभावित प्रतिकूल घटनाओं की एक सूची सूचीबद्ध करती है जिसमें रक्त और लसीका प्रणाली विकार, हृदय संबंधी विकार, आनुवंशिक विकार, अंतःस्रावी विकार, नेत्र विकार, प्रतिरक्षा प्रणाली विकार, तंत्रिका तंत्र विकार, गर्भावस्था प्रसवपूर्व और प्रसवकालीन स्थितियां, प्रजनन प्रणाली और शामिल हैं। स्तन विकार, संवहनी विकार और भी बहुत कुछ।

संयुक्त राज्य अमेरिका के VAERS (वैक्सीन प्रतिकूल घटना रिपोर्टिंग सिस्टम) डेटा के अनुसार, कोविड टीकों के लिए रिपोर्ट की गई प्रतिकूल घटनाएं इसकी स्थापना के बाद से सभी टीकों के लिए संयुक्त से अधिक है। यह हमारे लिए स्पष्ट है, इन अप्रयुक्त और प्रयोगात्मक कोविड टीकों के जोखिम उन लाभों से कहीं अधिक हैं जो वे प्रदान करने का दावा करते हैं।

एआईएम भारत सरकार से निम्नलिखित को लागू करने का आग्रह करता है:

- हम मांग करते हैं कि सभी कोविड वैक्सीन पीड़ितों या उनके परिवार के सदस्यों को भारत सरकार और वैक्सीन निर्माताओं द्वारा पर्याप्त मुआवजा दिया जाए।
- वैक्सीन से घायल लोगों और उनके परिवारों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और वैक्सीन कोर्ट का गठन किया जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय निगरानी लागू की जानी चाहिए कि वैक्सीन प्रतिकूल घटनाओं की यथाशीघ्र पहचान की जाए। शीघ्र उपचार प्रोटोकॉल बनाए जाने चाहिए और व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए ताकि जीवन बचाया जा सके।
- उन सभी अधिकारियों को, जिन्होंने झूठ बोला है, गुमराह किया है और भारतीय आबादी को कोविड के टीके लेने के लिए मजबूर किया है, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और भारत के नागरिकों की व्यापक मृत्यु और चोटों के लिए आपराधिक रूप से दंडित किया जाना चाहिए।

नागरिकों की सुरक्षा और भलाई हमेशा पहले होनी चाहिए।

मीडिया , पूछताछ के लिए कृपया संपर्क करें:

फ़िरोज़ मीठीबोरवाला - 9029277751

अंबर कोइरी - 9920903825

पृष्ठभूमि

1. गैर-कार्यात्मक AEFI निगरानी:

वैक्सीन के दुष्प्रभावों पर नज़र रखने के लिए भारत की प्रणाली स्पष्ट नहीं है। सरकार ने 2015 के दिशानिर्देशों को बदल दिया और इसके बजाय "संशोधित एईएफआई दिशानिर्देश: कार्यकारी सारांश" प्रकाशित किया। भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण हेरफेर एईएफआई दिशानिर्देशों में उन हिस्सों को छोड़ने में निहित है, जिसके लिए विशेष रूप से सरकार के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीकाकरण किए गए प्रत्येक व्यक्ति का सक्रिय रूप से पालन करने और सभी एईएफआई की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। नए नियम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से टीका लगवाने वाले सभी लोगों की जांच करने के लिए नहीं कहते हैं। यदि कोई शिकायत करता है तो उन्हें केवल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इस बदलाव का मतलब है कि गांवों और मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सक्रिय रूप से निगरानी करने की ज़रूरत नहीं है। वे दुष्प्रभाव तभी बताते हैं जब कोई उन्हें बताता है।

यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच प्रतिकूल घटना डेटा की तुलना करने पर, यह देखा जा सकता है कि भारत में कोविशील्ड प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या यूके की तुलना में लगभग 30 गुना है। हालाँकि, भारत में कोविशील्ड देने के बाद दर्ज की गई मौतें (1148 मौतें) ब्रिटेन में दर्ज की गई मौतों (2362 मौतें) से आधी से भी कम हैं। प्रतिकूल घटनाओं के यूके डेटा से निष्कर्ष निकालते हुए, भारत सरकार को टीकाकरण के बाद 39,793 मौतों और 1,13,75,583 चोटों की घोषणा करनी चाहिए थी, जबकि 1148 मौतें और 90,996 चोटें थीं। यह भारत सरकार द्वारा AEFI प्रणाली कार्यान्वयन के अस्वीकार्य रूप से खराब मानकों को इंगित करता है।

भारत सरकार जैकब पुलिएल बनाम यूओआई मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवमानना कर रही है, जिसने सरकार को संदिग्ध प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्ट करने और सभी एईएफआई रिपोर्टों को सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाने के लिए एक आभासी मंच के बारे में जागरूकता पैदा करने और फैलाने का निर्देश दिया है।

2. माननीय प्रधान मंत्री और अन्य अधिकारियों को बार-बार दी गई चेतावनियाँ:

माननीय प्रधान मंत्री को पिछले 3 वर्षों के दौरान डॉक्टरों, वकीलों, वैज्ञानिकों, कार्यकर्ताओं और चिंतित नागरिकों द्वारा लिखे गए विभिन्न पत्रों के माध्यम से बार-बार कोविड टीकों के खतरों के बारे में सलाह और चेतावनी दी गई है। प्रधानमंत्री को युवा वयस्कों में दिल के दौरे और कार्डियक अरेस्ट की बढ़ती संख्या के बारे में चेतावनी दी गई थी, साथ ही वैज्ञानिक डेटा और सहकर्मी की समीक्षा वाले शोध से इस तरह के संबंध की पुष्टि की गई थी।

देश के सभी शीर्ष विशेषज्ञ बाल चिकित्सा टीकाकरण के पक्ष में नहीं थे और इसके बावजूद, 15-18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15-18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके लगाने की घोषणा से एक दिन पहले, टीकाकरण अभियान के प्रमुख विनोद के. पॉल, आईसीएमआर प्रमुख बलराम भार्गव और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा था कि उनके निर्णय निर्देशित हैं। विज्ञान और बाल चिकित्सा टीकाकरण की आवश्यकता के लिए अभी तक कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। हम जानना चाहेंगे कि हमारे प्रधान मंत्री अपने स्वयं के विशेषज्ञों की सलाह के खिलाफ क्यों जाएंगे और उन बच्चों को टीका लगाने का एकतरफा फैसला क्यों करेंगे, जिनकी कोविड से बचने की दर 99.9973% है?

1500 से अधिक चिकित्सा विशेषज्ञों और संबंधित नागरिकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र माननीय प्रधान मंत्री को भेजा गया था जिसमें प्राथमिक मांग थी कि कोविड-19 टीकों के बड़े पैमाने पर वितरण को तुरंत रोका जाए।

3. कोविड वैक्सीन दुष्प्रभाव पर चल रहे अदालती मामले:

कोविड वैक्सीन के पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों ने देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामले दायर किए हैं। हालाँकि, भारतीय न्यायपालिका ने अपनी निष्क्रियता के कारण खोए गए बहुमूल्य जीवन पर ध्यान नहीं दिया है। जिन युवा वयस्कों की कोविड टीकाकरण के बाद अचानक मृत्यु हो गई, उनके माता-पिता भारत सरकार, वैक्सीन निर्माताओं और अनगिनत "विशेषज्ञों" द्वारा ठगा हुआ महसूस करते हैं, जिन्होंने अपने भ्रामक प्रचार के लिए बिना किसी जवाबदेही के इन असुरक्षित और प्रयोगात्मक टीकों को बढ़ावा दिया और कुछ मामलों में सुरक्षा के बारे में ज़बरदस्त झूठ बोला और कोविड टीकों की प्रभावकारिता। भारतीय न्यायपालिका ने भी रोते-बिलखते माता-पिता और प्रियजनों की पुकार को नजरअंदाज करना चुना है। नीचे कुछ मामले दिए गए हैं जो दायर किए गए हैं लेकिन अदालतों में उन्हें स्थानांतरित नहीं किया गया है:

- Rachana Gangu v. Union of India [Writ Petition (C) No. 1220 of 2021]
- Dilip Lunawat v. Serum Institute of India (P) Ltd. [Writ Petition (C) No. 2739/2022]
- Jean George & Anr v. Serum Institute Of India & Ors. [Writ Petition (C) No. 13573/2022]
- Sayeeda Vs Union of India [WP (C) No. 17628 of 2022]
- Smt. Kiran Yadav vs. The State of Maharashtra &Ors. Cri. WP No. 6159 of 2021

4. मानहानि का मामला:

अदार पूनावाला ने उन्हें "मास मर्डरर" कहने के लिए एआईएम सदस्यों योहान टेंगरा और अंबर कोइरी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया, जब वे पुणे में उन्हें हमदस्त नोटिस दे रहे थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने वास्तविक मुकदमे की सुनवाई होने तक योहान और अंबर के वीडियो हटाने का अंतरिम आदेश दिया है. न्यायाधीश रियाज़ छागला द्वारा दिया गया आदेश प्रति इन्क्यूरियम है। जज ने सुप्रीम कोर्ट के केस कानूनों का पालन नहीं किया और एक केस लॉ पर भरोसा किया, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने कानून की दृष्टि से खराब घोषित कर दिया है। एआईएम ने नागपुर उच्च न्यायालय में एआईएम और उसके सदस्य को बदनाम करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और अदार पूनावाला पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है। मुख्य मुकदमा अब बॉम्बे हाई कोर्ट में शुरू होगा. मार्च में SC की संविधान पीठ का आदेश आया है जिसमें कहा गया है कि अगर आरोपी कह रहा है कि उसके पास सबूत हैं और वह सच कह रहा है तो निषेधाज्ञा का आदेश नहीं दिया जा सकता। हैमडस्ट या अदालत का आदेश जो पुणे में अदार पूनावाला को दिया जा रहा था और जहां सामूहिक हत्यारा शब्द का इस्तेमाल किया गया था, अब सही साबित हो गया है क्योंकि डॉ. स्नेहल लुनावत की 21 मार्च को कोविशील्ड की पहली खुराक के बाद टीटीएस से मृत्यु हो गई थी।

5. सार्वजनिक स्वास्थ्य पर लाभ:

कोविड महामारी ने लॉकडाउन के माध्यम से आम आदमी की आजीविका और आय को नष्ट कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप अधिकारियों और नियामक निकायों के साथ-साथ फार्मास्युटिकल और वैक्सीन निर्माताओं को अप्रत्याशित लाभ हुआ है, जो हितों के टकराव में फंस गए हैं।

(Refer: https://awakenindiamovement.com/indias-covid-19-task-force-experts-exposed-conflicts-of-interest-in-our-public-health-system/)

सीरम इंस्टीट्यूट को अपने कोविड टीकों के माध्यम से 2 वर्षों में 4 बिलियन अमरीकी डालर (32,800 करोड़ रुपये) कमाने की उम्मीद थी, जबकि भारत बायोटेक को रु। महामारी के दौरान 22,500 करोड़ का मुनाफा हुआ। SII प्रति कोविड वैक्सीन खुराक से 2000% तक और भारत बायोटेक 4000% तक मुनाफा कमाता है। अदार पूनावाला ने यूके में 69,000 डॉलर प्रति सप्ताह की हवेली किराए पर ली, जबकि सरकार के लॉकडाउन उपायों के कारण लाखों लोग गरीबी में मजबूर हो गए।

6. चिकित्सीय विज्ञान की अनदेखी करते हुए वैक्सीन अनुसंधान पर करदाताओं के पैसे की बर्बादी:

भारत सरकार ने रु. का आवंटन किया है. वित्त वर्ष 21-2 में 39,000 करोड़ रु. वित्त वर्ष 22-23 में टीकों की खरीद के लिए 5000 करोड़ रुपये जबकि चिकित्सीय और प्राकृतिक और समग्र उपचार पर शोध के लिए एक भी रुपया खर्च नहीं किया गया। कोविड वायरस से कैसे निपटा जाए, इसके बारे में लगभग 3 वर्षों की सीख और खोजों के बाद, यह स्पष्ट है कि सुरक्षित, सस्ती और प्रभावी दवाओं और उपचार के तौर-तरीकों का उपयोग करके कोविड एक आसानी से प्रबंधनीय और इलाज योग्य बीमारी है।

ऐसे सभी उपचारों का संकलन यहां पाया जा सकता है:

https://awakenindiamovement.com/covid-cures/

7. कोविड टीकों का कपटपूर्ण और बेईमान जनादेश

जहां एक ओर भारत संघ ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों, आरटीआई और यहां तक कि MoHFW वेबसाइट पर दायर हलफनामों में बार-बार कहा है कि कोविड टीके स्वैच्छिक हैं और किसी को भी इन्हें लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर उन्होंने राज्यों और संस्थानों से कोविड टीकों को "सुनिश्चित" या "अनिवार्य" करने के लिए कहा है।
भारत सरकार के भीतर द्वंद्व और पाखंड के अलावा, हम कोविड टीकों के कारण होने वाली संभावित, मृत्यु-कारक प्रतिकूल घटनाओं के बारे में जानकारी को चूकने की निंदा करते हैं। अवेकन इंडिया मूवमेंट आयुर्वेद, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा आदि जैसी प्राकृतिक उपचार प्रणालियों और इससे भी महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रतिरक्षा की अनदेखी करने के लिए भारत सरकार के कार्यों की कड़ी निंदा करता है, जबकि टीके अनिवार्य थे और महामारी से लड़ने का एकमात्र तरीका माना जाता था।

8. सरकार ने भारत के लोगों से साफ़ झूठ बोला:

टीकों के 100% सुरक्षित और प्रभावी होने के साथ-साथ संक्रमण के प्रसार को सीमित करने की उनकी क्षमता के बारे में भारत सरकार द्वारा बार-बार किए गए दावे झूठे साबित हुए हैं। पहले, उन्होंने दावा किया कि टीकाकरण से संक्रमण से बचा जा सकेगा, लेकिन फिर भी लोग संक्रमित हो गए। फिर उन्होंने दावा किया कि इससे अस्पताल में भर्ती होने से बचा जा सकता है, लेकिन लोग फिर भी अस्पताल में भर्ती हुए।

फिर उन्होंने दावा किया कि इससे मृत्यु से बचा जा सकता है, फिर भी 2021-22 के बीच पूरी तरह से टीका लगाए गए लोगों की कोविड-19 से मृत्यु हो गई।

नवंबर 2021 में, बीएमसी ने दावा किया था कि उसने मुंबई की 100% आबादी को टीका लगाया है और फिर भी सिर्फ 3 महीने बाद, उन्होंने दावा किया कि ऑक्सीजन लेने वाले 96% कोविड मरीज़ पूरी तरह से टीकाकरण से वंचित थे। इसलिए, जब तक मुंबई में 3 महीनों में पूर्ण जनसंख्या मंथन नहीं हुआ, यह मान लेना सुरक्षित है कि बीएमसी ने अपने आंकड़ों के बारे में झूठ बोला है। कई अन्य अस्पतालों और सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से पता चला है कि अस्पतालों में टीकाकरण न कराने वालों की तुलना में टीका लगवाने वालों की संख्या अधिक है।

भारतीय न्यायालयों द्वारा इसकी और पुष्टि की गई, जिन्होंने फैसला सुनाया कि दूसरों को संक्रमित करने की उनकी क्षमता के संबंध में टीका लगाए गए और बिना टीकाकरण वाले व्यक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। यह जरूरी है कि जनता को उनके स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए सटीक जानकारी प्रदान की जाए।

अचानक होने वाली मौतों और कोविड टीकों के बीच संबंध को लेकर सरकार अब भी झूठ बोल रही है। आईसीएमआर ने हाल ही में एक अध्ययन प्रकाशित किया है जिसमें युवाओं की अस्पष्टीकृत अचानक मौतों में कोविड टीकों की भूमिका को उजागर किया गया है। यह अध्ययन स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण है और प्रदान की गई कार्यप्रणाली और डेटा में बड़े अंतराल के अलावा हितों के टकराव से घिरा हुआ है।

9. बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का प्रभाव:

बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को 72वीं संसदीय समिति की रिपोर्ट (राज्यसभा) में एचपीवी वैक्सीन के लिए अवैध और अनैतिक परीक्षणों के वित्तपोषण के लिए गंभीर रूप से दोषी ठहराया गया था, जहां 7 आदिवासी लड़कियों की मौत हो गई और अनगिनत अन्य लड़कियां घायल हो गईं और उनकी नसबंदी कर दी गई। फाउंडेशन का सभी सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर प्रभाव है और यह स्वास्थ्य और चिकित्सा पर अनुसंधान करने वाले हमारे विशेषज्ञ वैज्ञानिकों के अनुसंधान को वित्त पोषित करता है। यह MoHFW के तहत टीकाकरण तकनीकी सहायता इकाई में कई अधिकारियों के शोध को वित्त पोषित करता है, जिसे बदले में भारत के टीकाकरण कार्यक्रम को विकसित करने के साथ-साथ प्रतिकूल घटनाओं के बाद टीकाकरण (एईएफआई) प्रणाली का प्रबंधन करने का काम सौंपा जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फार्मास्युटिकल कंपनियों और वैक्सीन निर्माताओं के साथ फाउंडेशन के संबंधों से उत्पन्न हितों के संभावित टकराव के कारण केंद्र द्वारा बीएमजीएफ द्वारा आईटीएसयू की फंडिंग रोक दी गई थी। हालाँकि, यह महज दिखावा बनकर रह गया है क्योंकि आईटीएसयू के अन्य हिस्सों जैसे वैक्सीन कवरेज और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन को अभी भी फंडिंग मिल रही है।

10. वैश्विक महामारी संधि के खतरे और हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों पर WHO का प्रभाव:

वैश्विक महामारी संधि का प्रस्ताव हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के लिए गंभीर ख़तरा है। भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के प्रभाव की अवेकन इंडिया मूवमेंट द्वारा कोविड महामारी से निपटने और अवैज्ञानिक स्वास्थ्य नीतियों को बढ़ावा देने के लिए

आलोचना की गई है, जिससे भारत के नागरिकों को पीड़ा का अधिक खतरा है। यह संधि सदस्य देशों पर डब्ल्यूएचओ की पकड़ और शक्ति को और मजबूत करने के लिए एक उपकरण प्रतीत होती है, और यह एक तानाशाही के समान है, जो केवल अपने चुने हुए हस्तक्षेपों को आगे बढ़ाती है जो फार्मा लॉबी को लाभ पहुंचाते हैं। कृपया WHO और इसकी प्रस्तावित वैश्विक महामारी संधि पर अवेकन इंडिया मूवमेंट का स्थिति पत्र देखें:

https://awakenindiamovement.com/who-and-its-proposed-global-pandemic-treaty/

11. पब्लिक हेल्थ बिल:

राष्ट्रीय और राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित जनस्वास्थ्य विधेयक में लॉकडाउन, मास्किंग, और क्वारंटीन जैसी उपायों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम को बिना ध्यान में रखे बयान किया गया है। इसमें वैक्सीन के विपरीत प्रभावों और कोविड वैक्सीन निर्माताओं की ज़िम्मेदारी को ध्यान में नहीं रखा गया है। बल्कि, इसका उद्देश्य सरकारी शक्तियों को बढ़ाना है, जिससे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समर्थित पैंडेमिक और उपचार के तरीकों के अलावा वैकल्पिक दृष्टिकोणों को दमन किया जा सकता है। इस विधेयक की प्रावधानिकताएं वैश्विक पैंडेमिक संधि से पूर्व हैं और भारतीय नागरिकों पर अवैज्ञानिक स्वास्थ्य निर्देशों को कानूनी स्वीकृति प्रदान करती हैं। एआईएम ने इस विधेयक का विरोध किया है, चाहे यह राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तावित किया गया हो या केरल में इसकी मंजूरी दी गयी हो ।

12. कोविड वैक्सीन के लिए विषहरण प्रोटोकॉल:

अवेकन इंडिया मूवमेंट ने भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर के डॉक्टरों से विभिन्न वैक्सीन डिटॉक्स प्रोटोकॉल एकत्र किए हैं। घातक और स्थायी रूप से अक्षम करने वाले दुष्प्रभावों के बारे में मीडिया और सोशल मीडिया में मौजूदा डर के बावजूद, हमारा मानना है कि पर्याप्त ईमानदार और मेहनती डॉक्टर हैं जिन्होंने इन प्रायोगिक कोविड टीकों से होने वाले नुकसान का इलाज करने के लिए प्रोटोकॉल विकसित किए हैं। ये प्रोटोकॉल यहां पाए जा सकते हैं:
https://awakenindiamovement.com/did-you-take-the-covid-vaccine/